पेटीएम का मुनाफा 79 प्रतिशत बढ़ा

जून तिमाही में 220 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ, कारोबार बढ़ाने पर रहेगा कंपनी का फोकस

नयी दिल्ली, 21 जुलाई डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र की प्रमुख कंपनी पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के शानदार वित्तीय नतीजे पेश किए हैं. कंपनी का शुद्ध लाभ 79 प्रतिशत बढ़कर 220 करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह 123 करोड़ रुपये था.

मजबूत आय और बढ़ते कारोबार के दम पर कंपनी ने एक बार फिर निवेशकों का भरोसा जीता है. हालांकि, बोनस शेयर का इंतजार कर रहे निवेशकों को फिलहाल निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल ने अभी बोनस शेयर जारी नहीं करने का फैसला लिया है.कंपनी के अनुसार, फिलहाल उसका पूरा ध्यान कारोबार का विस्तार करने, लाभप्रदता बढ़ाने और दीर्घकाल में शेयरधारकों के लिए अधिक मूल्य सृजित करने पर है. इसी रणनीति के तहत निदेशक मंडल ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी में 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है.

> सिटी का कहना है कि कंपनी का परिचालन लाभ अनुमान से बेहतर रहा और क्लाउड खर्च में कमी तथा मर्चेंट लोन वितरण में वृद्धि से प्रदर्शन मजबूत हुआ है. वहीं सीएलएसए ने 'कमजोर प्रदर्शन' की रेटिंग बनाए रखते हुए 1,050 रुपये का लक्ष्य मूल्य दिया है. उसका मानना है कि भविष्य में परिचालन खर्च बढ़ने से मुनाफे पर कुछ दबाव रह सकता है. पेटीएम लगातार बेहतर वित्तीय प्रदर्शन कर रही है और अब उसका ध्यान अल्पकालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक विकास पर है. बोनस शेयर टालने का फैसला भले ही कुछ निवेशकों को निराश करे, लेकिन कारोबार में निवेश और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार की रणनीति भविष्य में कंपनी और उसके शेयरधारकों के लिए अधिक लाभदायक साबित हो सकती है.

ईरान-अमेरिका तनाव से भारत का तेल आयात बिल 77% बढ़ा

नयी दिल्ली, 21 जुलाई पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखाई देने लगा है.

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 77 प्रतिशत बढ़कर 4.64 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और आपूर्ति में बाधा के कारण भारत को तेल खरीदने पर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 2.02 लाख करोड़ रुपये अधिक खर्च करने पड़े., ईरान-अमेरिका संघर्ष के चलते हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी रहीं. इस दौरान भारत ने तेल आयात की मात्रा में लगभग 4.5 प्रतिशत की कमी की, लेकिन ऊंची कीमतों के कारण कुल आयात बिल में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, भारत ने आपूर्ति बनाए रखने के लिए अन्य देशों से भी अतिरिक्त खरीदारी की. अंतरराष्ट्रीय बाजार में फिलहाल ब्रेंट क्रूड करीब 88.56 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड लगभग 82.22 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.

डब्ल्यूटीओ मत्स्य सब्सिडी समझौते में शामिल हुआ भारत

छोटे और पारंपरिक मछुआरों के हितों को मिलेगा संरक्षण

वैश्विक बाजार में भारत की साख होगी मजबूत

नयी दिल्ली, 21 जुलाई भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मत्स्य सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार कर वैश्विक स्तर पर टिकाऊ मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर मजबूत किया है.

वाणिज्य सचिव ने सोमवार को डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस सौंपा, जिसके साथ ही भारत इस समझौते को स्वीकार करने वाला 123वां सदस्य देश बन गया. इस कदम को भारत के मत्स्य क्षेत्र, समुद्री पर्यावरण और छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. डब्ल्यूटीओ के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में जून 2022 में सर्वसम्मति से अपनाया गया यह समझौता पर्यावरणीय स्थिरता को केंद्र में रखकर बनाया गया संगठन का पहला बहुपक्षीय व्यापार समझौता है. दो-तिहाई सदस्य देशों की मंजूरी मिलने के बाद यह 15 सितंबर 2025 से प्रभावी हुआ.

इसका उद्देश्य समुद्र में अवैध, अनियमित और बिना रिपोर्ट की जाने वाली (आईयूयू) मछली पकड़ने की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर रोक लगाना और समुद्री जैव संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करना है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार यह समझौता केवल समुद्री मत्स्य पालन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर लागू होगा. एक्वाकल्चर (मत्स्य पालन) और अंतर्देशीय मत्स्य पालन को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. इसका अर्थ है कि भारत का झींगा उत्पादन समुद्री खाद्य निर्यात, जो मुख्य रूप से एक्वाकल्चर पर आधारित है, इस समझौते से प्रभावित नहीं होगा. इससे भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा भी बरकरार रहेगी.

> इन व्यवस्थाओं से छोटे और पारंपरिक मछुआरों के हित सुरक्षित रहते हुए समुद्री जैव विविधता का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा. डब्ल्यूटीओ मत्स्य सब्सिडी समझौते में भारत की भागीदारी न केवल जिम्मेदार समुद्री शासन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी, बल्कि नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में भारत की भूमिका को भी और सशक्त बनाएगी.

पेंशन नियमों में बदलाव की तैयारी

पुराने प्रावधानों में बदलाव से समय पर मिलेगी पेंशन

नयी दिल्ली, 21 जुलाई सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन मिलने में आने वाली परेशानियों और बढ़ते कानूनी विवादों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार पेंशन नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है.

सरकार का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में कई ऐसे पुराने प्रावधान हैं, जो समय के साथ अप्रासंगिक हो चुके हैं और इन्हीं की वजह से पेंशन से जुड़े कई मामले अदालतों तक पहुंच रहे हैं. ऐसे में नियमों की व्यापक समीक्षा कर उन्हें अधिक सरल, पारदर्शी और समयानुकूल बनाने पर विचार किया जा रहा है.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन मुकदमों पर आयोजित दूसरी कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 'जीरो लिटिगेशन पेंशन इकोसिस्टम' विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है.

उनका कहना था कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की नौबत नहीं आनी चाहिए. इसके लिए ऐसे सभी नियमों की समीक्षा की जाएगी, जो अनावश्यक विवाद और कानूनी अड़चनें पैदा करते हैं.उन्होंने कहा कि कई पेंशन नियम वर्षों पहले बनाए गए थे.

राहुल हिमालियन बने आईआरसीटीसी के कार्यवाहक

नई दिल्ली, 21 जुलाई. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) श्री संजय कुमार जैन के त्यागपत्र के उपरांत, रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी के निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) श्री राहुल हिमालियन को आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है.

भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) के वर्ष 1999 बैच के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित अधिकारी श्री राहुल हिमालियन को भारतीय रेल एवं आईआरसीटीसी में 26 वर्षों से अधिक का समृद्ध एवं विविध अनुभव प्राप्त है. वे 16 फरवरी, 2024 से रेल मंत्रालय के अधीन अनुसूची 'ए' नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आईआरसीटीसी के निदेशक मंडल में पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) के रूप में वे पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास, अवसंरचना, प्रशासन तथा राजभाषा जैसे महत्वपूर्ण विभागों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं.हिमालियन का शैक्षणिक जीवन भी अत्यंत उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायक रहा है. वे द लॉरेंस स्कूल के हेड बॉय एवं सर्वश्रेष्ठ छात्र रहे. उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर से विद्युत अभियांत्रिकी में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक उपाधि प्राप्त की तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली से अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि 10.00 सीजीपीए के साथ अर्जित की. उन्हें सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण छात्र के रूप में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है.

> 20 जुलाई, 2026 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के साथ ही श्री राहुल हिमालियन आईआरसीटीसी के समग्र संचालन एवं रणनीतिक नेतृत्व का दायित्व संभालेंगे. साथ ही वे निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) के रूप में अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करते रहेंगे. आईआरसीटीसी परिवार श्री राहुल हिमालियन को इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता है तथा विश्वास व्यक्त करता है कि उनके दूरदर्शी एवं सक्षम नेतृत्व में संगठन सेवा, नवाचार तथा उत्कृष्टता के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा.

उज्जीवन का 'आइवरी': प्रीमियम बैंकिंग में बदलाव

भोपाल, 21 जुलाई भारत में तेजी से बढ़ रहा 'मास-एफ्लूएंट' यानि उच्च-मध्यम आय वर्ग अब बैंकिंग सेक्टर की दिशा बदल रहा है. बढ़ती आय, निवेश के प्रति बढ़ती रुचि और बेहतर जीवनशैली की चाह रखने वाला यह वर्ग अब सिर्फ बचत खाते और लेन-देन की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहना चाहता.

यही वजह है कि बैंक भी अब पारंपरिक सेवाओं से आगे बढ़कर ऐसे समाधान पेश कर रहे हैं, जो ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों के साथ-साथ उनकी जीवनशैली से भी जुड़ते हों. ग्राहकों की इन बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम 'आइवरी' के माध्यम से बैंकिंग और लाइफस्टाइल अनुभव को एक साथ जोड़ रहा है. समर्पित रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रीमियम मेटल डेबिट कार्ड, वैश्विक सुविधाओं तक पहुँच, लाइफस्टाइल लाभों और एकीकृत रिवॉर्ड्स जैसी सुविधाओं के साथ 'आइवरी' ग्राहकों को पारंपरिक बैंकिंग से आगे बढ़कर एक समग्र अनुभव देने का प्रयास कर रहा है. भारत में बढ़ती आय, कारोबार और उद्यमिता के नए अवसरों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते इस्तेमाल ने 'मास-एफ्लूएंट' वर्ग को तेजी से आगे बढ़ाया है. पारंपरिक बैंकिंग ग्राहकों और अत्यधिक संपन्न लोगों के बीच आने वाला यह वर्ग आज खर्च, निवेश और बैंकिंग से जुड़ी अपनी पसंद के जरिए नए ट्रेंड तय कर रहा है. यह वर्ग तकनीक को अच्छी तरह समझता है, अपने पैसों को लेकर जागरूक है और हर फैसले में बेहतर वैल्यू की उम्मीद रखता है.

स्थानीय सपनों से वैश्विक करियर तक छात्रों के लिए मुफ्त एसएपी लर्निंग

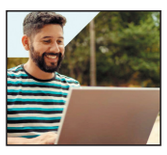

भोपाल,21 जुलाई एक समय था, जब नौकरी पाने के लिए सिर्फ एक डिग्री ही काफी मानी जाती थी. लेकिन, आज का दौर बदल चुका है. अब कंपनियाँ ऐसे ग्रेजुएट्स की तलाश में हैं, जो नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को तेजी से ढाल सकें और वैश्विक स्तर पर आत्मविश्वास के साथ काम कर सकें. आज कार्यस्थलों की बदलती जरूरतें पारंपरिक शिक्षा से कहीं आगे निकल चुकी हैं. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए, एसएपी लर्निंग हब, स्टूडेंट एडिशन तैयार किया गया है. इसके तहत भारत के पात्र अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को एकेडमिक वेरिफिकेशन के बाद बिना किसी सब्सक्रिप्शन के प्रीमियम एसएपी लर्निंग रिसोर्सेस का फ्री एक्सेस मिलता है.इस प्रोग्राम में फाइनेंस, सप्लाई चेन, एचआर एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए लर्निंग जर्नीज़, विशेषज्ञों द्वारा संचालित सेशंस, हैंड्स-ऑन प्रैक्टिस सिस्टम्स और एसएपी सर्टिफिकेशन परीक्षा के दो अटेम्प्ट्स शामिल हैं.

यूरोप में चीनी उत्पादों पर कड़ी सख्ती

ईयू की सख्ती से भारतीय निर्यातकों के लिए बढ़ेंगे नए अवसर

खिलौने, कॉस्मेटिक्स और टेक्सटाइल सेक्टर को मिल सकता है बड़ा लाभ

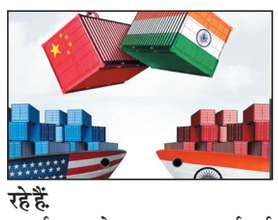

नयी दिल्ली, 21 जुलाई यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा चीन की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा समूह के प्लेटफॉर्म पर 550 मिलियन यूरो करीब 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड जुर्माना लगाए जाने के बाद भारतीय कारोबारियों और निर्यातकों के लिए नए अवसरों के द्वार खुलते दिखाई दे रहे हैं.

ईयू ने यह कार्रवाई अलीएक्सप्रेस पर नकली, असुरक्षित और नियमों के विपरीत उत्पादों की बिक्री रोकने में विफल रहने के आरोप में की है. विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप का यह सख्त रुख भारत के खिलौना, कॉस्मेटिक्स, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग के लिए बड़े अवसर लेकर आ सकता है. यूरोपीय आयोग की जांच में सामने आया कि अलीएक्सप्रेस पर ऐसे उत्पाद बेचे जा रहे थे जो यूरोप के सुरक्षा और पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करते थे. कई मामलों में गैरकानूनी और प्रतिबंधित उत्पादों की पहचान होने के बाद भी उन्हें प्लेटफॉर्म से समय पर नहीं हटाया गया. इसी आधार पर यूरोपीय संघ ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया. आयोग ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

समाचार विशेष

चुनावी मोड़ में आ गईं मायावती

100 सीटों के लिए बनाया खास प्लान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है. इसके लिए सभी सियासी दल कमर कस रहे हैं. अब विधानसभा 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी प्रमुख मायावती ने सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर फोकस किया है उन्होंने 100 सीटों के लिए खास प्लान बनाया है. अब देखना होगा कि सपा या भाजपा किसकी मुश्किल बढ़ने वाली है.

सूत्रों के मुताबिक, मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जुलाई महीने में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मंडल की करीब 100 विधानसभा सीटों में से 30 से 35 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए जाएं. इनमें से करीब 15 नामों पर सहमति भी बन चुकी है और उनकी स्थानीय स्तर पर घोषणा की तैयारी चल रही है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में मायावती ने बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, सदस्यता अभियान की समीक्षा करने और साफ-सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. साथ ही सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया.

बसपा की परंपरा के मुताबिक, पहले चयनित नेताओं को विधानसभा प्रभारी बनाया जाता है और चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उन्हें आधिकारिक प्रत्याशी घोषित किया जाता है. सूत्रों का कहना है कि मायावती चाहती हैं कि 403 में से आधे से ज्यादा सीटों पर जल्द उम्मीदवार तय हो जाएं, ताकि वे समय रहते अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार और संगठन को मजबूत कर सकें.

चुनावी शतरंज बिछानी शुरू

बसपा की तैयारियों पर भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हर दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कई दल सक्रिय होते हैं, लेकिन जनता ने सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकारें भी देखी हैं और अब योगी आदित्यनाथ सरकार के काम को भी देख रही है. उनके अनुसार, जनता विकास और भाजपा के साथ है. वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को अपने संगठन को मजबूत करने का लोकतांत्रिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि हर पार्टी चुनाव की तैयारी करती है और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है. यानी 2027 का चुनाव को लेकर बसपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी शतरंज बिछानी शुरू कर दी है.

भाजपा में नए प्रादेशिक क्षत्रप बन रहे

योगी, फड़नवीस, सरमा ने अपना वर्चस्व स्थापित किया

नई दिल्ली. अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की भाजपा में कई प्रादेशिक क्षत्रप थे. ये क्षत्रप अपने केंद्रीय नेतृत्व का सम्मान तो करते थे लेकिन उनके भरोसे राजनीति नहीं करते थे. अपने प्रदेश की राजनीति में उनका अपना असर होता था.

कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा उस जमाने के एकमात्र क्षत्रप हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी ताकत बचा कर रखी है. कम से कम इस समय तक भाजपा का सर्वशक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व येदियुरप्पा को माइनस करके कर्नाटक की राजनीति नहीं कर पा रहा है. उनके अलावा बाकी क्षत्रपों का राजनीतिक असर समाप्त हो चुका है. मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, राजस्थान में वसुंधरा राजे, हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल आदि अब अपने प्रदेश की राजनीति में चीजें निर्धारित नहीं करते हैं. वाजपेयी और आडवाणी के जमाने के बड़े क्षत्रपों में से एक नरेंद्र मोदी 12 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बन गए. उसके बाद से प्रादेशिक क्षत्रपों की ताकत धीरे धीरे समाप्त हो गई. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा के नए क्षत्रप उभर रहे हैं.

मोहन यादव हुए मजबूत

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम इसमें सबसे चौंकाने वाला है. जानकार सूत्रों का कहना है कि मोहन यादव पिछले ढाई साल में इतने मजबूत हुए हैं कि प्रदेश के तमाम बड़े नेता चिंता में हैं. वैसे उनको मुख्यमंत्री बनाते समय ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश के बड़े नेताओं नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रह्लाद सिंह पटेल आदि को किनारे कर दिया था. उमा भारती पहले से किनारे हैं और अब कहा जा रहा है कि मोहन यादव ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की टिकट कटवाई है.

बहुमत भाजपा का, बाजी मार गई कांग्रेस

करसोग (मंडी). हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंचायत समिति करसोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव ने मंडी जिले की राजनीति में नया संदेश दिया है.

स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भाजपा समर्थित खेमा पंचायत समिति की दोनों शीर्ष कुर्सियां बचाने में असफल रही, जबकि कांग्रेस ने संख्या बल में पिछड़ने के बावजूद दोनों पद अपने नाम कर लिए. चुनाव परिणाम के बाद क्षेत्र में क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी असंतोष को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित इशरा मेहता और उपाध्यक्ष पद पर कली चौहान ने एक-एक वोट के अंतर से जीत दर्ज की.

परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे रणनीतिक सफलता और बेहतर राजनीतिक प्रबंधन का परिणाम बताया. उधर, भाजपा ने हार के कारणों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है. करसोग पंचायत समिति के 15 सदस्यीय सदन में भाजपा समर्थित 10 सदस्य, कांग्रेस समर्थित चार सदस्य और एक निर्दलीय सदस्य निर्वाचित हुआ था.

विशेष | कई मौजूदा विधायकों के समक्ष संकट, टिकट पर लटकी तलवार!

बीजेपी का सर्वे बढ़ा रहा विधायकों का सिरदर्द

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी का पूरा फोकस इस बार सिर्फ चुनाव जीतने पर नहीं, बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी (हैट्रिक) करने पर है. इसी रणनीति के तहत बीजेपी दिल्ली और लखनऊ स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से सर्वे करा रही है.

इन सर्वे के जरिए मौजूदा विधायकों के प्रदर्शन, जनता में उनकी स्वीकार्यता और संभावित नए दावेदारों की स्थिति का आकलन किया जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक अब तक तीन सर्वे पूरे हो चुके हैं, जबकि दो और सर्वे प्रस्तावित हैं. हालांकि यदि विधानसभा चुनाव तय समय से पहले, यानी 2026 के अंत में कराए जाते हैं, तो सितंबर में प्रस्तावित चौथा सर्वे ही अंतिम माना जा सकता है. ऐसे में कई मौजूदा विधायकों, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की टिकट को लेकर सियासी बेचैनी बढ़ गई है.

बीजेपी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले कुल पांच चरणों में सर्वे कराने की योजना बनाई गई है. इन सर्वे का उद्देश्य सिर्फ मौजूदा विधायकों की लोकप्रियता मापना नहीं, बल्कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, संगठन की मजबूती और जनता की प्राथमिकताओं को समझना भी है. संगठन का मानना है कि समय रहते फीडबैक मिलने से उम्मीदवार चयन अधिक प्रभावी होगा और चुनावी रणनीति को भी जमीनी हकीकत के अनुरूप तैयार किया जा सकेगा.

बूथ से बाजार तक जुटाया जा रहा फीडबैक-पार्टी के एक प्रदेश पदाधिकारी के अनुसार, यह पूरी तरह संगठनात्मक और आंतरिक प्रक्रिया है. सर्वे एजेंसियां बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक अलग-अलग वर्गों के लोगों से बातचीत कर रही हैं. फीडबैक लेने वालों में व्यापारी, पेशेवर, महिलाएं, युवा, ठेला-रेहड़ी संचालक, किसान, सामाजिक संगठन, पार्टी के मोर्चों और प्रकोष्ठों से जुड़े कार्यकर्ता सहित विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं. उद्देश्य यह जानना है कि जनता अपने विधायक और पार्टी के कामकाज को किस नजरिए से देख रही है.

लोकसभा चुनाव से लिया जा रहा सबक

बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं होने की एक बड़ी वजह कई सांसदों के प्रति जनता की नाराजगी भी रही. उस समय क्षेत्रीय स्तर पर निष्क्रियता और जनता से दूरी जैसी शिकायतों के बावजूद कई सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया था, जिसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ा. इसी अनुभव को देखते हुए पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में अधिक सतर्क दिखाई दे रही है.